बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 180 ● नई दिल्ली ● शनिवार 02 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली में बेटी को पीटने से बचाने पर ससुर की चाकू गोदकर हत्या, थप्पड़ मार पहली मंजिल से घसीटते हुए गली में ले गया

पूर्वी दिल्ली। सीमापुरी इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जहां एक युवक ने अपने ही ससुर की चाकू से कई वार करके बेरहमी से हत्या कर दी। ससुर का कसूर इतना था कि उन्होंने बेटी को दामाद से पीटने से बचाया था। जरा सी बात पर भड़के दामाद ने पहले ससुर को थप्पड़ मारा। उसके बाद उन्हें पहली मंजिल से घसीटते हुए नीचे गली तक ले गया, जहां उसे चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर जान ले ली। आरोप है युवक पहली मंजिल से घसीटते हुए नीचे लाया और गली में चाकू से वार कर दिए। मृतक की पहचान राम जतन (50) के रूप में हुई है। सीमापुरी थाना ने शव को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के भाषण नफरत फैलाने वाले नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर की अपील खारिज

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कोई भी संज्ञेय अपराध नहीं बनता। यह फैसला 29 अप्रैल को जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने सुनाया। अदालत ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का अंतिम निष्कर्ष सही था, लेकिन उसकी तर्क प्रक्रिया (सैंक्शन के आधार पर) पूरी तरह उचित नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एफआईआर दर्ज करने के लिए पहले से सरकारी अनुमति (सैंक्शन) जरूरी नहीं है। ऐसी अनुमति की आवश्यकता केवल उस चरण में होती है, जब अदालत मामले का संज्ञान लेती है। यदि जांच शुरू करने से पहले ही सैंक्शन को अनिवार्य कर दिया जाए, तो इससे जांच प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि हेट स्पीच संविधान की भाईचारे की भावना के खिलाफ है और समाज की नैतिक संरचना को कमजोर करती है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि मौजूदा कानून इस मुद्दे से निपटने के लिए पर्याप्त हैं और नए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। मामला 2020 में दिल्ली के शाहीन बाग में हुए एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान दिए गए कथित भाषणों से जुड़ा था। अनुराग ठाकुर ने जहां देश के गद्दारों को... वाली बात कही थी, वहीं प्रवेश वर्मा ने चेतावनी दी थी कि अगर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका गया, तो वह आखिरकार घरों में घुसकर बलात्कार और हत्या करेंगे। जिसके बाद सीपीआई(एम) नेताओं बृंदा करात और के एम तिवारी ने आरोप लगाया था कि 27 और 28 जनवरी 2020 को अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा ने भड़काऊ भाषण दिए थे। इसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने अगस्त 2020 में इस शिकायत को खारिज कर दिया था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 2022 में याचिका को खारिज कर दिया।

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस- सीएम रेखा गुप्ता ने बांटी सुरक्षा व शिक्षा किट; 35,000 श्रमिकों को मिलेगा यह लाभ

नई दिल्ली । मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिकों को बधाई दी और दिल्ली के कर्मयोगियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर 1,000 निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा किट तथा 100 श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा किट प्रदान की। 35,000 श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की कौशल विकास पहल भी शुरू हुई। सरकार ने निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क माफ किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, राष्ट्र निर्माण में अपनी अमूल्य भूमिका निभाने वाले सभी श्रमिक भाइयों-बहनों को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

शुक्रवार को श्रमिक सम्मान समारोह में सम्मिलित होकर कर्मयोगी साथियों को नमन करने का अवसर मिला। कार्यक्रम में 1000 निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा किट और श्रमिक परिवारों के 100 बच्चों को शिक्षा किट प्रदान की गई, साथ ही हर वर्ष 35,000 श्रमिकों को प्रशिक्षित करने वाले बड़े स्तर के कौशल विकास अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने श्रमयोगियों के सम्मान को शासन की सोच और नीति के केंद्र में स्थापित किया है। उनके मार्गदर्शन में 'विकसित भारत' का संकल्प श्रमिक सशक्तिकरण से ही आगे बढ़ता है, जहां हर श्रमिक सुरक्षित, सम्मानित और अवसरों से जुड़ा हो। सीएम ने कहा, हमारी सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क को पूर्णतः माफ किया जा रहा है। सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से श्रमिक परिवारों को सम्मानपूर्ण सहयोग मिलेगा। साथ ही, आधुनिक लेबर चौक और श्रमिक सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से आवश्यक सेवाएं सीधे श्रमिकों तक पहुंचेंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी अग्रिम जमानत

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में 30 अप्रैल 2026 को लंबी बहस के बाद जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपना निर्णय सुनाया। पवन खेड़ा ने कानूनी कार्यवाही के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहाँ से अब उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल गई है।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें

पवन खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने असम सरकार के रुख की कड़ी आलोचना की। सिंघवी ने कहा कि यदि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने किसी संवैधानिक पदाधिकारी को संवैधानिक चरवाहे की तरह व्यवहार करते देखा होता, तो वे व्यथित हो जाते। उन्होंने तर्क दिया कि मानहानि के मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। खेड़ा के देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है, तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर अपमानित क्यों किया जा रहा है? सिंघवी ने दावा किया कि जालसाजी (धारा 339, BNS) के आरोप बाद में दुर्भावनापूर्ण तरीके से जोड़े गए, जबकि मूल प्राथमिकी में इनका उल्लेख नहीं था।

सरकार का पक्ष और सॉलिसिटर जनरल की दलील

असम सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हिरासत में पूछताछ का समर्थन किया। मेहता ने आरोप लगाया कि यह मामला आधिकारिक दस्तावेजों के फर्जी निर्माण से जुड़ा है। जांच में सामने आया है कि पासपोर्ट सील और क्यूआर कोड जैसे आधिकारिक चिह्नों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि ये दस्तावेज किसने तैयार किए और क्या इस साजिश में अन्य लोग या कोई ÷विदेशी लिंक÷ भी शामिल है, विशेषकर चुनाव के समय। उन्होंने आरोप लगाया कि खेड़ा जांच से बच रहे हैं और अधिकारियों की पहुंच से बाहर रहकर वीडियो जारी कर रहे हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला तब शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि रिनिकी भुइयां सरमा के पास कई विदेशी पासपोर्ट और अघोषित विदेशी संपत्ति है। इसके बाद रिनिकी भुइयां सरमा ने खेड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुरुआत में उन्हें ट्रांजिट बेल दी थी, लेकिन बाद में मामला गौहाटी उच्च न्यायालय और अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने अब खेड़ा को राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उनकी स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है।

हमारे फैसले सोनिया गांधी लेती हैं, कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव को लेकर खरगे का बड़ा बयान

नई दिल्ली । कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल सिद्धारमैया ही सीएम रहेंगे। हालांकि, अपने बयान में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि हमारे फैसले सोनिया गांधी लेती हैं। उनके बयान को लेकर भाजपा ने उन्हें कटघरें में लाकर खड़ा कर दिया है। यहां तक कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने तक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खरगे ने कहा कि मुख्यमंत्री पद में बदलाव की बात हर दिन होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अध्यक्ष के रूप में वह, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मिलकर यह निर्णय लेंगे। कांग्रेस आलाकमान प्रमुख संगठनात्मक और राजनीतिक मामलों पर निर्णय से पहले वरिष्ठ नेतृत्व से परामर्श करता है। खरगे ने कहा कि वे सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर जोर देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी की भागीदारी के बिना कोई निर्णय नहीं होता। आलाकमान के भीतर व्यापक चर्चा होती है और वरिष्ठ नेताओं से परामर्श किया जाता है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है, इसलिए किसी भी बदलाव पर अटकलें लगाना जल्दबाजी होगी। खरगे ने आगे कहा कि एक बार निर्णय लेने के बाद यह कर्नाटक के सर्वोत्तम हित में होगा। उन्होंने सभी से पार्टी नेतृत्व के अंतिम निर्णय का सम्मान करने का आग्रह किया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार नेतृत्व-साझाकरण व्यवस्था को लेकर आंतरिक मतभेदों का सामना कर रही है। यह विशेष रूप से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थकों के बीच है। पार्टी के कुछ वर्गों ने कथित 2023 के सत्ता-साझाकरण समझौते का हवाला देते हुए शिवकुमार को शेष कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है।

हौज खास डियर पार्क से घटाई जाए हिरणों की भीड़, सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश

नई दिल्ली । दिल्ली के हौज खास स्थित ए एन झा डियर पार्क में हिरणों की बढ़ती संख्या और सीमित संसाधनों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। 27 अप्रैल को दिए गए फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि पार्क में अधिकतम 38 हिरण ही रखे जा सकते हैं, जबकि शेष को चरणबद्ध तरीके से उपयुक्त वन्यजीव अभयारण्यों में स्थानांतरित किया जाएगा। यह प्रक्रिया केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की निगरानी में तय वैज्ञानिक मानकों के अनुसार पूरी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि हिरण जैसे वन्यजीवों को सामान्य परिस्थितियों में पिंजरों या सीमित बाड़ों में रखना न तो कानूनी रूप से उचित है और न ही पारिस्थितिक दृष्टि से। अदालत ने कहा कि केवल अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही ऐसी व्यवस्था स्वीकार्य हो सकती है। यह टिप्पणी वन्यजीव संरक्षण के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित करती है, जिनमें जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना प्राथमिकता माना जाता है।न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व आदेश को बरकरार रखते हुए उसे अंतिम रूप दे दिया।अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया कि वह पार्क में बचे हिरणों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षित स्टाफ सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि डियर पार्क का संरक्षित वन का दर्जा कायम रहना चाहिए और इसे किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं किया जाना

चाहिए। अदालत ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सीईसी द्वारा तैयार किए गए वन्यजीव स्थानांतरण संबंधी वैज्ञानिक दिशानिर्देशों की समीक्षा करे और आवश्यक संशोधनों के साथ उन्हें छह महीने के भीतर लागू करने पर विचार करे। इन दिशानिर्देशों में पशुओं की पहचान और टैगिंग, सुरक्षित परिवहन, पशु चिकित्सा देखभाल, उपयुक्त आवास का चयन और स्थानांतरण के बाद निगरानी जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। ये मानक अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं, जो वैश्विक स्तर पर वन्यजीव संरक्षण के लिए मान्यता प्राप्त संस्था है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि डियर पार्क का मिनी जू का दर्जा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण पहले ही रद्द कर चुका है और 2021 में इसका लाइसेंस समाप्त हो गया था। ऐसे में बिना वैध मान्यता के बड़ी संख्या में वन्यजीवों को रखना कानूनी रूप से भी उचित नहीं माना गया।सीईसी ने स्थानांतरण के लिए राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का निरीक्षण भी किया है,

जिन्हें संभावित पुनर्वास स्थलों के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया तय मानकों के अनुसार और मानवीय तरीके से की जानी चाहिए।इस मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है, जिसमें अदालत निर्देशों के पालन की स्थिति की समीक्षा करेगी। यह फैसला एक बार फिर इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि वन्यजीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही सबसे प्रभावी और टिकाऊ तरीके से संभव है। अदालत ने 26 नवंबर 2025 को सीईसी को डियर पार्क का विस्तृत सर्वे करने का निर्देश दिया था। 6 मार्च 2026 को सौंपी गई रिपोर्ट में पार्क की वहन क्षमता (इकोलॉजिकल कैपेसिटी) यानी किसी क्षेत्र में सीमित संसाधनों के आधार पर कितने जीव सुरक्षित रह सकते हैं, का आकलन किया गया।रिपोर्ट में पाया गया कि हिरणों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ गई है, क्योंकि जन्म नियंत्रण और नसबंदी जैसे उपाय प्रभावी रूप से लागू नहीं किए गए। इसके अलावा चारे की उपलब्धता, पशु चिकित्सा सुविधाओं और बाड़ों की स्थिति भी पर्याप्त नहीं पाई गई।

ईरान युद्ध की असली कीमत- बढ़ता आर्थिक दबाव

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने केवल सैन्य और कूटनीतिक मोर्चों पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक स्तर पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, इस युद्ध पर अमेरिका द्वारा किए गए खर्च को लेकर भारी असमंजस और बहस जारी है। आधिकारिक तौर पर जहां लगभग 25 अरब डॉलर खर्च होने की बात कही जा रही है, वहीं कई विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट्स इस आंकड़े को 40 से 50 अरब डॉलर तक बता रहे हैं। यह अंतर न केवल आंकड़ों की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आधुनिक युद्ध कितने महंगे और जटिल हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में शुरू हुए इस सैन्य अभियान का उद्देश्य ईरान पर दबाव बनाना और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना बताया गया था। लेकिन जैसे-जैसे यह संघर्ष आगे बढ़ा, इसकी लागत और प्रभाव दोनों ही उम्मीद से कहीं अधिक बड़े होते चले गए। पेंटागन के अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती आठ हफ्तों में ही लगभग 25 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। लेकिन यह आंकड़ा अधूरा माना जा रहा है क्योंकि इसमें सैन्य ठिकानों की मरम्मत, उपकरणों की क्षति और अन्य अप्रत्यक्ष खर्च शामिल नहीं हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। बहरीन, कुवैत, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों में स्थित कम से कम नौ अमेरिकी बेस प्रभावित हुए हैं। इन ठिकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण पर अरबों डॉलर खर्च होने की संभावना है। इसके अलावा, नागरिक और ऊर्जा ढांचे को हुए नुकसान की भरपाई भी एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकती है। इस युद्ध की एक खास बात यह है कि इसमें असममित युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल किया गया है। ईरान ने अपेक्षाकृत सस्ते ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग कर अमेरिका को महंगे रक्षा तंत्र का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। उदाहरण के तौर पर, ईरान के एक ड्रोन की कीमत जहां लगभग 20,000 से 50,000 डॉलर होती है, वहीं उसे मार गिराने के लिए अमेरिका को पैट्रियट जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख डॉलर तक होती है। इस तरह के असंतुलन ने अमेरिका के सैन्य बजट पर भारी दबाव डाला है। इसके अलावा, अमेरिका द्वारा इस्तेमाल की गई टॉमहॉक मिसाइलें, जिनकी कीमत लगभग 36 लाख डॉलर प्रति मिसाइल है, और थाड सिस्टम के रडार, जिनकी कीमत 500 मिलियन से 1 अरब डॉलर तक होती है, इस युद्ध को और अधिक महंगा बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका ने अब तक 1,200 से अधिक इंटरसेप्टर मिसाइलें और 1,000 से अधिक टॉमहॉक मिसाइलें इस्तेमाल की हैं, जो उसके वार्षिक उत्पादन से भी अधिक है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में इन हथियारों की भरपाई के लिए भी भारी खर्च करना पड़ेगा। युद्ध की लागत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है–अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव। इस संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ा है। खासकर विकासशील देशों के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बन गई है, जो पहले से ही आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कई सांसदों ने इस खर्च की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और सरकार से स्पष्ट आंकड़े प्रस्तुत करने की मांग की है। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की समय सीमा नजदीक आने के साथ ही यह बहस और तेज हो सकती है कि क्या अमेरिका को इस युद्ध को जारी रखना चाहिए या नहीं। वहीं, पेंटागन ने अभी तक पूरी लागत का स्पष्ट आकलन नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति का मूल्यांकन जारी है और अंतिम आंकड़े सामने आने में समय लगेगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह युद्ध अमेरिका के लिए एक महंगा सौदा साबित हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू है–रणनीतिक लाभ और हानि का संतुलन। अमेरिका ने भले ही ईरान पर सैन्य दबाव बनाया हो, लेकिन इसके बदले उसे भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है। दूसरी ओर, ईरान ने अपेक्षाकृत कम संसाधनों में अमेरिका को चुनौती दी है, जो उसकी रणनीतिक सफलता को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस युद्ध के प्रभाव व्यापक हैं। मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ी है, जिससे वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर असर पड़ा है। कई देशों ने इस संघर्ष को लेकर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अंततः, यह स्पष्ट है कि अमेरिका-ईरान संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं, बल्कि एक वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक चुनौती बन चुका है। इस युद्ध की वास्तविक लागत केवल डॉलर में नहीं मापी जा सकती, बल्कि इसके सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय प्रभाव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो इसकी लागत और भी बढ़ सकती है, जिससे न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि कूटनीतिक समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाएं, ताकि इस महंगे और विनाशकारी संघर्ष को रोका जा सके।

4 मई के बाद बदल जाएगी देश की राजनीति

देश के चार राज्यों- असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल एवं एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम एग्जिट पोल भी सामने आ चुके है। इस बार का विधानसभा चुनाव , इस मायने में बहुत खास है कि इसमें देश के दो प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों-कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और एआईएडीएमके जैसे ताकतवर क्षेत्रीय दलों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। सबसे बड़ा सवाल तो लेफ्ट फ्रंट के दलों के सामने खड़ा हो गया है क्योंकि केरल की सत्ता हाथ से जाते ही उनके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में तो लेफ्ट पार्टियां पहले ही साफ हो चुकी है। जाहिर है कि इन पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजें सिर्फ इन राज्यों के मुख्यमंत्री ही तय नहीं करेंगे बल्कि दोनों गठबंधन- एनडीए, एवं इंडिया को भी प्रभावित करेंगे। यह भी एक तथ्य है कि चाहे, चुनावी नतीजे जो भी आए लेकिन इसके बाद देश के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में तेजी से बड़े बदलाव दिखाई देने लगेंगे। बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर कई महीने पहले ही बदलाव की शुरुआत कर दी थी लेकिन वह बदलाव अभी संगठन के ढांचे और सरकार तक नहीं पहुंच पाया है। बताया जा रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद नितिन नवीन की नई टीम के गठन के लिए उच्चस्तरीय बैठकों का दौर शुरू होगा। बीजेपी आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि जो बुजुर्ग हो चुके नेताओं को संगठन से बाहर रहने के लिए कैसे मना पाते है क्योंकि सबसे युवा अध्यक्ष चुनने के बाद पार्टी उनकी टीम को भी युवा नेताओं से ही भरना चाहती है। पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बीजेपी को पार्टी का फैसला लेने वाली सर्वोच्च ईकाई संसदीय बोर्ड, उम्मीदवारों का चयन करने वाली केंद्रीय चुनाव समिति के साथ ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों और मोर्चों का पुनर्गठन करना है। पार्टी में नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया सहित विभिन्न विभागों की टीम के साथ ही राष्ट्रीय मोर्चों का भी पुनर्गठन करना है। इसके बाद बदलाव की यही प्रक्रिया सरकार और राज्यों में भी की जानी है। नई टीम में एक तरफ जहां युवा और अनुभवी नेताओं का संतुलन बनाना होगा वहीं महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा जगह देनी होगी। बताया जा रहा है कि 4 मई को चुनावी नतीजे आने के 10-15 दिनों के अंदर नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो सकता है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय का पूरा स्वरूप ही बदला-बदला नजर आएगा। कांग्रेस में भी बड़े पैमाने पर बदलाव की शुरुआत आने वाले दिनों में होने जा रही है। मोदी-शाह की जोड़ी ने 46 वर्ष के नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राहुल और सोनिया गांधी के सामने दुविधा की स्थिति पैदा कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे सुलझे हुए परिपक्व नेता तो है लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को भी एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ युवा नेताओं की टीम तो खड़ी करनी ही पड़ेगी। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अभी भी इस बात पर अड़े हुए है कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। ऐसे में जाहिर से बात है कि कांग्रेस को राहुल और प्रियंका गांधी से इतर जाकर अन्य युवा नेताओं की तरफ देखना पड़ेगा। इस रेस में फिलहाल सचिन पायलट सबसे आगे बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों के चहेते नेता सचिन पायलट को आने वाले दिनों में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, अगर अशोक गहलोत ने पार्टी के बुजुर्ग नेताओं के साथ मिलकर कोई और खेला नहीं कर दिया तो। ध्यान दीजिएगा कि, यह अकारण नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से गहलोत बार-बार पायलट की बगावत का किस्सा सुनाने में लगे हुए है। लेकिन अगर पायलट का नाम पीछे छूट भी गया तो भी राहुल गांधी को पार्टी के लिए नया और वो भी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ढूंढना ही पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की गुटबाजी पर लगाम कसने के लिए खड़गे को मुख्यमंत्री बनाकर बेंगलुरु भेजा जा सकता है और उनकी जगह पर दिल्ली में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठाया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर खड़गे कर्नाटक जाएंगे तो फिर पार्टी को राज्यसभा में भी अपना नया नेता चुनना पड़ेगा। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय संगठन महासचिव भी किसी युवा नेता को ही बनाना पड़ेगा और उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में भी नए चेहरों की संख्या बढ़ जाएगी। यह तय मान कर चलिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में मई के महीने में ही बदलाव होना तय है। हालांकि कांग्रेस में बदलाव की यह रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है।

सम्पादकीय...

पाकिस्तान का दांव- ईरान के लिए खोले 6 जमीनी व्यापार मार्ग

पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव ने एक नया मोड़ ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होरमुज जलडमरूमध्य में लागू की गई नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। इस नाकेबंदी का उद्देश्य केवल ईरान के तेल निर्यात को रोकना नहीं, बल्कि उसके आयात और वैश्विक व्यापार तक पहुंच को भी बाधित करना है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने एक रणनीतिक कदम उठाते हुए छह प्रमुख जमीनी व्यापार मार्ग खोलकर इस नाकेबंदी में एक तरह से छेद कर दिया है, जिसने पूरे क्षेत्रीय समीकरण को बदल दिया है। होरमुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अमेरिका द्वारा 13 अप्रैल से लागू की गई नाकेबंदी के चलते ईरान के बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कई जहाजों को रोका गया है, कुछ को जब्त भी किया गया है। इस कारण ईरान के व्यापार प्रवाह में भारी बाधा आई है और उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ गया है। ईरान, जो पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहा था, इस नाकेबंदी के बाद और अधिक संकट में आ गया। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई और वैश्विक बाजारों तक उसकी पहुंच सीमित हो गई। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरान आर्थिक रूप से ढह रहा है और नकदी की भारी कमी का सामना कर रहा है। इस तरह की स्थिति में नाकेबंदी ईरान के लिए आर्थिक घेराबंदी का काम कर रही है। लेकिन इसी तनावपूर्ण माहौल में पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस्लामाबाद ने छह जमीनी ट्रांजिट रूट्स को सक्रिय कर दिया, जो उसके प्रमुख बंदरगाहों–ग्वादर, कराची और पोर्ट कासिम–को ईरान की सीमा से जोड़ते हैं। इन मार्गों के जरिए अब सामान समुद्री रास्तों के बजाय जमीन के रास्ते ईरान पहुंचाया जा रहा है। खासकर वे हजारों कंटेनर, जो कराची बंदरगाह पर फंसे हुए थे, अब इन नए रास्तों से भेजे जा रहे हैं। इन मार्गों में ग्वादर-गब्द, कराची/पोर्ट कासिम से गब्द, ताफ्तान, और खैबर-पख्तूनख्वा से जुड़े कई रास्ते शामिल हैं। ये सभी मार्ग पाकिस्तान और ईरान के बीच 900 किलोमीटर लंबी सीमा को जोड़ते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संपर्क मजबूत होता है। इस पहल को पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक वैधानिक आदेश के तहत कानूनी रूप दिया गया है, जिसमें तीसरे देशों के सामान को पाकिस्तान के जरिए ईरान ले जाने की अनुमति दी गई है। यह कदम केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान ने इस कदम के जरिए खुद को एक क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। साथ ही, यह चीन समर्थित ग्वादर बंदरगाह परियोजना को भी मजबूती देता है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का एक अहम हिस्सा है। भू-राजनीतिक विश्लेषक हिमांशु जैन ने इस कदम को एक टर्निंग पॉइंट बताया। उनके अनुसार, पाकिस्तान ने कानूनी रूप से अमेरिकी नाकेबंदी में एक बड़ा छेद कर दिया है। वहीं ऊर्जा द्विवेदी का कहना है कि पाकिस्तान एक साथ कई भूमिकाएं निभा रहा है।

बदलती ग्लोबल गेम और भारत

पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता अभी तक बेनतीजा है। इसका एक और प्रभाव भी है जिससे दुनिया चकित है और भारत नाखुश है, यह पाकिस्तान को मिली भूमिका है। पाकिस्तान के नेता विशेष तौर पर फील्ड मार्शल असीम मुनीर बहुत सक्रिय हैं और दोनों अमेरिका और ईरान के बीच पुल का काम कर रहे है। डोनॉल्ड ट्रम्प तो मुनीर को 'माई फेवरिट फील्ड मार्शल' कह चुके हैं'। मुनीर एकमात्र सैनिक अधिकारी है जिसे व्हाइट हाउस में लंच के लिए आमंत्रित किया गया है। पर ईरान का नेतृत्व भी पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयास के बारे कृतज्ञता प्रकट कर चुका है। ईरानियन रैवल्यूशनरी गार्ड के साथ मुनीर के घनिष्ठ सम्बन्ध है। पाक सेना के प्रमुख का महत्व बहुत बढ़ गया है और पाकिस्तान का नागरिक नेतृत्व पीछे पड़ गया है जिसके उस देश और हमारे लिए असुखद परिणाम हो सकते हैं। इस वक्त तो हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का प्रायोजक माना जाता था, शान्ति का प्रयास कर रहा है। इसी देश की एबटाबाद सैनिक छावनी में ओसामा बिन लादेन वर्षों छिपा रहा था। पहलगाम की घटना को मुश्किल से एक साल ही हुआ है, पर दुनिया उसे भूल गई है और पाकिस्तान के कथित मध्यस्थता के प्रयास की प्रशंसा हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया ने पाकिस्तान के आतंकी अतीत को भुला दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो तीन साल से जेल में है और जिसके बारे बताया जा रहा है कि नज़र जा रही है, इमरान के बेटे सुलेमान इमरान खान ने कहा है कि, इन्हें ग्लोबल समुदाय के सामने अपनी छवि को व्हाइट- वॉश करने के मौका मिल गया है। दुनिया पहली बार पाकिस्तान को एक प्रकार के शान्ति दूत की भूमिका में देख रही है। यह नया अनुभव है। इस युद्ध से सब तंग है और जो भी इसे रोकने का प्रयास करेगा उसे प्रशंसा मिलेगी ही। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने लिखा है, पाकिस्तान की प्रासंगिकता वास्तविक है। उन्होंने अपने भूगोल, सम्बंधों और राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाते हुए खुद को कूटनीति के केन्द्र में स्थापित कर लिया है,पर इनका प्रभाव सीमित है। वह इकट्ठा कर सकते है, संदेशों का आदान- प्रदान कर सकते है, पर यह नहीं तय कर सकते कि नतीजा क्या हो। वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार रज़ा रूमी ने भी लिखा है, पाकिस्तान की भूमिका की सीमा स्पष्ट है- वह वार्ता करवा सकते हैं, पर पालन नहीं करवा सकते। पाकिस्तान मध्यस्थ कम संदेशवाहक अधिक है, पर वह इस संदेश वाहक की भूमिका से ही संतुष्ट है। आखिर यह वही देश है जो कुछ वर्ष पहले तक जिसे 'डॉग-हाउस' कहा जाता है, में था। अचानक वह लाइमलाइट में आ गया है। यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने कूटनीतिक फुर्ती दिखाई है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चीन के साथ उनकी 'लौह-दोस्ती' है। ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं तो साऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला समझा जाएगा। पर पाकिस्तान की एक और हकीकत भी है। वह फटेहाल है और उनका नेतृत्व कह चुका है कि 'हम अंतर्राष्ट्रीय भीखमंगे बन चुके हैं'। जर्जर हालत के कारण मध्य पूर्व का संकट उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। वहां जो पाकिस्तानी काम कर रहे है वह 20 अरब डालर भेजते है। अगर युद्ध अधिक चला तो यह पैसा और लोगों का रोजगार संकट में पड़ जाएगा। यूएई ने अपना 3 अरब डालर का कर्ज़ा वापिस मांग कर संकट खड़ा कर दिया था, पर पाकिस्तान की कूटनीतिक दक्षता ऐसी है कि सऊदी अरब ने तत्काल 5 अरब डालर का कर्ज़ा दे कर पाकिस्तान को डूबने से बचा लिया है। पाकिस्तान को अपने पश्चिमी बार्डर की भी चिन्ता है जहां बलूच बागी चुनौती दे रहे हैं और जहां से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गुजरता है। इसलिए भी वह चाहते हैं कि यह टकराव जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इस सारे घटनाक्रम का एक और पहलू भी है, वह हमारा अलगाव है। हमारे पड़ोस में टकराव चल रहा है जो हमारे हितों पर चोट पहुंचा रहा है, पर हमारी कोई भूमिका नहीं है। मुरली मनोहर जोशी ने तो माना है कि 'हम विश्वगुरु थे, पर अब नहीं रहे'। यह क्यों हुआ?इज़राइल के साथ हमारे घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। वह रक्षा पार्टनर है जबकि ईरान हमारी भूगौलिक हकीकत है। चाहबहार के रास्ते हम मध्य एशिया से सम्बंध मज़बूत करना चाहते थे, पर हम एक तरफ झुक गए और ईरान का विश्वास खो बैठे। जब अयातुल्ला खामेनेई की मौत हुई तो हमने शोक भी प्रकट नहीं किया। ईरान पर हमले के बारे हमारी शुरुआती खामोशी ने बहुत नुक्सान किया है। मुनीर को गोद में बैठाते समय ट्रम्प ने हमारी भावनाओं की चिन्ता नहीं की। आशा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब इस बदतमीज़ शख्स को 'माई फ्रेंडकहनाबंदकरसके दोस्त नहीं है, जो बात पाकिस्तान नेतृत्व को भी पता लग जाएगा। ट्रम्प 'यूज़ एंड थ्रो' में विश्वास रखते हैं। एक और कारण है कि विश्व राजनीति की ज़मीन बदल गई है। पहले चीन के साथ अमेरिका का टकराव प्रमुख विवाद था जिसके लिए अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी। क्वाड को इतना महत्व इसीलिए दिया गया था,पर अचानक ट्रम्प की दिलचस्पी बदल गई। वह अगले महीने चीन जा रहे है और उनकी कोशिश है कि चीन के साथ व्यावहारिक रिश्ता क़ायम हो सके। चीन ने भी अपने पत्ते बहुत अच्छी तरह से खेले हैं। ट्रम्प की कलाबाजियों के कारण चीन का प्रभाव बढ़ा है। जहां तक क्वाड का सवाल है, दो साल से शिखर सम्मेलन नहीं हुआ। यह भारत में होना है, पर सम्भावना नज़र नहीं आती। किसी को इस संगठन में दिलचस्पी नहीं लगती। हडसन इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ विशेषज्ञ कैन मोरियामु ने लिखा है कि क्वाड मर चुका है क्योंकि महाशक्तियों की स्पर्धा इंडो-पैसिफिक से हट चुकी है और यूरो-एशिया की तरफ चली गई है। भारत का महत्व खत्म नहीं हुआ, पर इस समय यह कम हो गया है क्योंकि गेम बदल गया है। युद्ध को लेकर जो ज़बरदस्त कूटनीति चल रही है, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। पूर्व विदेश सचिव और राजदूत विवेक काटजू ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह लम्हा जब टैरर सब की प्राथमिकता थी, निकल गया है। पश्चिम के देशों को आतंकवाद से कोई खतरा नहीं है। उनकी बात सही है। अल क़ायदा जैसे संगठन जो पश्चिमी देशों पर हमला करते थे, खत्म हो चुके हैं। हमास, हिज़बुल्लाह मध्य पूर्व तक सीमित हैं। पाकिस्तान ने भी सबक़ सीख लिया। वह हमारे खिलाफ़ आतंक जारी रखेगा, पर पश्चिमी देशों को निशाना नहीं बनाएगा। वह यह रोना रो रहे हैं कि हम तो खुद आतंक का शिकार हैं। इस सब का हमारे लिए क्या मायने है? एक, दुनिया को हमारी शिकायतों में दिलचस्पी नहीं रही। वह केवल यह चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का टकराव नियंत्रण से बाहर न निकल जाए क्योंकि दोनों परमाणु शक्तियां हैं। दुनिया यूक्रेन और ईरान के युद्ध में व्यस्त है, हमें तवज्जो नहीं मिल रही। हमें नई नीति बनानी होगी और दुनिया को स्पष्ट करना होगा कि अगर हम पर आतंक का वार होता है तो हमें मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। मोदी सरकार कह ही चुकी है कि हम पर आतंकी हरकत को 'एक्ट ऑफ वॉर' समझा जाएगा। और इसकी सम्भावना को रद्द नहीं किया जा सकता। इतिहास को याद रखना चाहिए। 1971 में निक्सन के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर चुपचाप पाकिस्तान से चीन गए थे जिसके बाद अमेरिका और चीन के सम्बंध बेहतर हो गए और पाकिस्तान को यह ईनाम मिला कि उसके परमाणु कार्यक्रम के प्रति पश्चिम ने आंखें मूंद लीं। उसी के बाद हमारे खिलाफ़ आतंकी घटनाओं की बाढ़ आ गई। इस बार पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को आमने-सामने लाने में सफल रहा है। देखना है कि इस बार उन्हें क्या ईनाम मिलता है? एक दबंग पाकिस्तान हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकता है। अमेरिका के पूर्व राजदूत कैनेथ जस्टर ने कहा है, अगर भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हमला होता है तो भारत को अपनी प्रतिक्रिया सीमित करनी पड़ सकती है क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे सम्बंध हैं। ट्रम्प के आशीर्वाद से पाकिस्तान अपना परमाणु ज़खीरा बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी सहयोग की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपनी विदेश नीति और प्रासंगिकता को फिर से तय करने का समय आ गया है। इस वर्ष भारत में ब्रिक्स सम्मेलन है, पर वहां से भी अच्छे समाचार नहीं आ रहे कि हम बहुमत की राय से अलग हैं। हमारे लिए यह निर्णायक क्षण है। हमें अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को क़ायम रखना है और यह संदेश नहीं देना कि हमने अपनी पारम्परिक तटस्थता छोड़ दी है। दूसरा, यह भी निश्चित करना है कि हमारी खामोशी हमारे सिद्धांतों और आस्थाओं से अधिक ऊंची सुनाई न दे।

इंसान, मेहनत और अदृश्य संघर्ष

डा मुमताज शीरीन

दुनिया जब अपने अस्तित्व को एक व्यवस्थित ढंग से समझना चाहती है तो वह खुद को एक मुकम्मल रूप से पेश करती है ऐसा रूप जो देखने समझने और महसूस करने के काबिल हो। हम जब जिंदगी को छूते हैं तो हमें उसकी सतह पर एक नरमी महसूस होती है, लेकिन उसी नरमी के नीचे एक कठोर सच्चाई छुपी होती है, जो मेहनत के पसीने से तर जमीन पर इकट्ठा होकर अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां तरक्की की रफ्तार हैरत अंगेज है इऊंची ऊंची इमारतें, नई टेक्नोलॉजी, तेज रफ्तार जिंदगी सब कुछ अपनी जगह मौजूद है लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरक्की में मजदूर भी बराबरी से शामिल है ? इसी संघर्ष की याद में हर साल 1 मई International Workers Day मनाया जाता है। यह दिन हमें यह एहसास दिलाता है कि मजदूर सिर्फ एक काम करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज की आधारशिला है। और मेहनत से ही शहर बसते हैं इमारतें खड़ी होती हैं और दुनिया आगे बढ़ती है । लेकिन अफसोस की बात है कि मजदूर को अक्सर उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता है । यदि श्रम को केवल शारीरिक परिश्रम समझा जाए, तो उसकी अवमानना होगी । श्रम वास्तव में एक दर्शन है एक ऐसा विचार जो मनुष्य को उसकी मूल पहचान से जोड़ता है। यह किसी एक मत या विचारधारा पर निर्भर नहीं, बल्कि मानवता के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है । यही वह श्रमिक है जो पत्थर को भवन में बदलता है, मिट्टी को जीवन देता है और अपने पसीने से संसार को सींचता है । यदि श्रमिक पुरुष है, तो उसका परिश्रम दिखाई देता है उसे एक पहचान मिलती है किंतु यदि वही श्रमिक महिला है तो उसका श्रम प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है। जबकि वह घर बाहर दोनों स्थानों पर कार्य करती है, फिर भी न उसको सम्मान मिलता है न पहचान , ना ही उसका अधिकार । हमारे समाज की यह विडंबना है कि महिला के श्रम को कर्तव्य समझ लिया जाता है कार्य नहीं । जब कोई बच्चा श्रम करने के लिए विवश होता है तो केवल अपना बचपन ही नहीं खोता बल्कि अपना भविष्य भी दांव पर लगा देता है । जिस समय उसे विद्यालय में होना चाहिए वह जीवन का बोझ उठाने के लिए मजबूर है । साहित्य ने सदैव श्रमिक को अपना विषय बनाया है कभी सहानुभूति के साथ तो कभी विरोध के स्वर में । किंतु मूल प्रश्न आज भी वही है । कि क्या साहित्य केवल दर्पण है, यह वह परिवर्तन की चिंगारी भी बन सकता है । और शायद यही वह मार्ग है, जहां से एक बेहतर और न्याय पूर्ण संसार की शुरुआत होती है । यह समस्याएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वास्तव में एक सभ्य समाज हैं । यदि हम इस महान विचार को समझने का केवल औपचारिक अवसर प्रदान करते हैं तो, इसकी महत्ता केवल एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह सकती क्योंकि यह एक निरंतर बौद्धिक और आत्मिक जागरण है एक ऐसा चेतन विकास, जिसमें मनुष्य अपने आसपास की वस्तुओं को केवल उपयोग की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में देखता है ।

अगर हम इस सत्य को जीवन में उतार लें तो हमें इस दिशा मे दैनिक बोध होगा कि मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है किसी विशेष अनुग्रह का परिणाम नहीं है वरन एक लंबी और कठिन परिश्रम का फल है ।जिन बातों को हम अपनी स्वाभाविक विरासत समझते आए है वे दरअसल एक क्रम से जुड़ी हुई श्रृंखला है, " रोटी, कपड़ा और मकान"भले ही यह तीनो अलग अलग हों परन्तु वास्तव में निरंतर श्रृंखला का हिस्सा है । यही वे मूल भूत आवश्यकता है जिसके बिना मानव का जीवन संभव नहीं और यही वे प्रश्न है जो मजदूर के हाथों की लकीरों में लिखे होते है वह मेहनत जो खेत से बाजार तक, बाजार से घर तक, और घर से जीवन तक पहुंचती है । इस पूरी प्रक्रिया में मजदूर हर जगह मौजूद हैकभी मिट्टी के पास, कभी धुएं के बीच, कभी तपती धूप में अपने पसीने के साथ, तो कभी बारिश और सर्द रातों में वह अपने अस्तित्व को श्रम में ढालता है और हमारे जीवन के तंत्र को गति देता है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी आधारित है । यदि हम इस समझ को अपने भीतर जगह दे तो, शायद हमें यह आभास हो कि मजदूर कोई अलग अस्तित्व नहीं बल्कि वह सदियों से हमारी आवश्यकताओं का हिस्सा रहा है ।

और हमारी सुविधाओं से जुड़ा हुआ है,और हमारी सुख सुविधाओं की नींव उसके पसीने और परिश्रम पर आश्रित है । तब शायद हम उसके दुखों को भी इस गर्माहट से महसूस कर सकेंगे जिस गर्माहट से हम उसकी मेहनत से मिलने वाली सुविधाओं का आनंद लेते हैं । मजदूर का पसीना केवल पानी नहीं है ह परिश्रम का एक पवित्र प्रतीक है एक ऐसा प्रतीक जो हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया की हर सुविधा किसी ना किसी मेहनत का परिणाम है । यदि हम सच में एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते है, तो हमें मजदूर को केवल एक वर्ग नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखना होगा ।

वही मजदूर जो हमारे घरों की छत बनाते हैं मगर उनके घरों की छत टपकती है, हमारे लिए अनाज उगाते हैं मगर उनके घर अक्सर खाने को रोटी नहीं होती , वे दूसरों के घरों में उजाला भरते है लेकिन त्योहारों की हर चमक उनके हाथों से कहीं छूट जाती है। पर विडंबना यह है कि जिन हाथों ने संसार के बहुत से घरों को आबाद किया उनके अपने घर के अक्सर सूने रह जाते हैं । दीवारें चुपचाप अपनी दरारों का दुख सहती है, और मौसम का हर बदलाव उनके लिए एक नई चिंता लेकर आता है। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो मानव जीवन की पूरी धुरी ही हिल जाती है और उम्मीदें धीरे-धीरे चूल्हे की आंच तरह मंद पड़ जाती है और बुझ जाती हैं। क्यों कि उनके पास सुरक्षित कल की गारंटी नहीं है। यह विडंबना ही है जो दूसरों के जीवन में खुशियां भरते हैं वह अपने जीवन में अभाव का बोझ ढोते ढोते मर जाते हैं। । यह विरोधाभास कोई संयोग नहीं यह हमारी सामूहिक असंवेदनशीलता की उपज है । जिसने हमारे भीतर की मानवीय चेतना के इस स्रोत को बेड़ियों के सांचे में ढाल दिया है । यदि हम अपने अस्तित्व की तह में उतरकर , इस भूले बिसरे स्रोत को फिर से छू सकें । जहां संवेदना अभी भी धीमी सी सांस ले रही है तू शायद हमें यह एहसास हो कि यह दुनिया केवल हमारे सुख का विस्तार नहीं है, बल्कि अनगिनत अदृश्य श्रम और त्याग से रची हुई एक जीवित सच्चाई है । एक समृद्ध और स्वस्थ समाज वही होता है जहां मेहनतकश को केवल न्याय ही नहीं मिलता बल्कि उसके अस्तित्व को सम्मान भी दिया जाए, क्यो किसी भी सभ्यता की ऊंचाई उसके महलों से नहीं उसके मेहनतकशों के सम्मान से आंकी जाती है। मजदूर का पसीना केवल पानी नहीं होता बल्कि वह एक पवित्र प्रतीक है, दुनिया की हर राहत, हर सुविधा इनकी की अथक मेहनत का परिणाम है। यदि हम एक बेहतर समाज की रचना करना चाहते हैं तो हमें मजदूर को केवल एक वर्ग के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखना होगा । तभी शायद हम यह कह सकेंगे कि हमने " एक मई" को सिर्फ मजदूर दिवस के रूप में मनाया नहीं है बल्कि इस को समझा भी है ।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/[illegible])

बहादुर बिटिया के साहस से लुटेरे गिरफ्तार,एसएसपी ने किया सम्मानित

गोरखपुर। थाना गोला क्षेत्र के अंतर्गत स्थित देवाश स्वर्ण कला केन्द्र में 27 अप्रैल को हुई लूट की कोशिश को दुकान संचालक की सूझबूझ और साहस ने विफल कर दिया। दुकान का संचालन पिता-पुत्री द्वारा किया जाता है, जहां उस दिन दो अज्ञात युवक ग्राहक बनकर पहुंचे और चांदी की अंगूठी खरीदने का बहाना करने लगे। जैसे ही अमृता वर्मा उन्हें अंगूठी दिखाने लगीं, उसी दौरान दोनों युवकों ने मौके का फायदा उठाते हुए पास में रखा झाली का पुड़िया उठाया और भागने का प्रयास किया। अचानक हुई इस घटना के बावजूद अमृता वर्मा ने घबराने के बजाय अदम्य साहस, धैर्य और सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने चोरों का डटकर सामना किया और स्थिति को संभालने की कोशिश की, जिससे घटना और बड़ी नहीं हो सकी। घटना की सूचना मिलते ही गोरखपुर पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 36 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस तेज और प्रभावी कार्रवाई की भी सराहना की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर ने अमृता वर्मा के साहसिक कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बहादुरी न सिर्फ समाज के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी देती है।

बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही विश्व में शांति संभव - केशव प्रसाद मौर्य

बुद्ध विहारों व आंबेडकर स्मारकों के संरक्षण के लिए सरकार संकल्पित - बृजेश पाठक

कुशीनगर।

बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भगवान बुद्ध का शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश आज पूरे विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब दुनिया अशांति और संघर्ष के दौर से गुजर रही है, तब भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर ही स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को युद्ध नहीं, बल्कि बुद्ध का संदेश दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला रहा है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती समेत भगवान बुद्ध से जुड़े

पवित्र स्थलों का अभूतपूर्व विकास हुआ है और इन्हें अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान मिली है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है, ताकि देश-विदेश से आने वाले बौद्ध श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने बौद्ध अनुयायियों से भगवान बुद्ध के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि भगवान बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है और किसी भी संघर्ष का स्थायी समाधान युद्ध नहीं, बल्कि बुद्ध के विचारों में निहित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों, बुद्ध विहारों, स्मारकों तथा बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर से संबंधित स्मृति स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र की निधि से बुद्ध व आंबेडकर स्मारकों के विकास में सहयोग करें, ताकि इन स्थलों को और बेहतर स्वरूप दिया जा सके।

इस अवसर पर दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने बुद्ध पूर्णिमा और अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं दीं। कुशीनगर आगमन पर दोनों उपमुख्यमंत्रियों का प्रशासनिक अधिकारियों व बौद्ध भिक्षु संघ द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, बौद्ध अनुयायी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

बिजली की चपेट में आकर लाइनमैन गंभीर रूप से झुलसा, गोरखपुर रेफर

कप्तानगंज, कुशीनगर। शुक्रवार को कप्तानगंज क्षेत्र में एक बड़ा हादसा उस समय हो गया जब विद्युत विभाग का एक संविदा लाइनमैन करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के अनुसार, विद्युत सब स्टेशन कप्तानगंज पर संविदा कार्यरत महेश कन्नौजिया (25 वर्ष), पुत्र शंकर प्रसाद, निवासी गिदहा चक बैरिया थाना अहिरौली, कुशीनगर, ग्राम कारीतीन में 11000 वोल्ट की लाइन पर कार्य कर रहे थे। बताया जा रहा है कि लाइनमैन ने कार्य शुरू करने से पहले सीडाउन (लाइन बंद) लिया था और पोल पर चढ़कर मरम्मत कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक विद्युत आपूर्ति चालू हो गई, जिससे वह तेज करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल लाइनमैन को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

मजदूर दिवस पर 'सहायक सदस्य दिवस' फन-एन-लर्न स्कूल में श्रमिकों का सम्मान

उपहार देकर जताया आभार, प्रबंध निदेशक निहाल ए. खान बोले- श्रमिक समाज की रीढ़

गोरखपुर।

जाफरा बाजार स्थित फन-एन-लर्न स्कूल में मजदूर दिवस को 'सहायक सदस्य दिवस' के रूप में मनाते हुए श्रमिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंध निदेशक निहाल ए. खान ने संस्थान में कार्यरत सभी श्रमिकों को उपहार भेंट कर उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निहाल ए. खान ने कहा कि मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य नई पीढ़ी के मन में कार्यस्थलों पर सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, शिक्षा के माध्यम से हर कोई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उन्होंने श्रमिकों को समाज की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनके बिना देश का विकास संभव नहीं है, इसलिए उनके बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। स्कूल की सहायक प्रबंध निदेशक सीमा निहाल ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के श्रमिकों का सम्मान करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का भेदभाव न पनपे। उत्तराधिकारी ताबिश निहाल ने भी श्रमिकों के सम्मान में दिए गए उपहार को सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि यह कदम समाज में सकारात्मक संदेश देता है। वहीं वाइस प्रिंसिपल रीना प्रसाद ने इसे एक अनूठी मिसाल बताते हुए कहा कि श्रमिकों का सम्मान करना संस्था की श्रेष्ठ सोच को दर्शाता है। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष शिफा खान, प्रिंसिपल रूमाना जबीं, इरफान अहमद खान, शबनम अख्तर खान, योति जायसवाल, अनीता अग्रवाल सहित विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

विश्व श्रमिक दिवस पर वन विभाग द्वारा श्रमिकों को किया गया सम्मानित

आनंदनगर महाराजगंज ।

वन क्षेत्र फरेंदा में एक मयी विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर दैनिक श्रमिकों को क्षेत्रीय वन अधिकारी सुशील कुमार चतुर्वेदी द्वारा आवश्यक किट देकर सम्मानित किया गया। विश्व श्रमिक दिवस पर वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को सम्मानित करने के पश्चात क्षेत्रीय वन अधिकारी सुशील कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि श्रमिकों से ही सर्वाधिक कार्यों का निष्पादन किया जाता है। उन्होंने कहा कि श्रमिक सभी क्षेत्रों में कार्य करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन कर अग्रणी भूमिका निभाते हैं सबको श्रमिकों का सम्मान करना चाहिए। विश्व श्रमिक दिवस पर वन क्षेत्र में कार्य कर रहे दैनिक कर्मचारी एवं अन्य श्रमिकों को आवश्यक किट देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर क्षेत्रीय वन अधिकारी सुशील कुमार चतुर्वेदी, उपवन क्षेत्रीय अधिकारी अरुण कुमार सिंह, वन दरोगा अनिल सिंह, विजय कुमार ,मनोज यादव सुरेंद्र मौर्य ,भाटी सहित सभी बनकर्मी मौजूद रहे।

पुलिस शव को कब्र से निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस टीम की ओर से की कार्रवाई

महराजगंज।

निचलौल थाना क्षेत्र के भारत नेपाल बार्डर से सटे मटरा धमउर गांव शुक्रवार को पुलिस टीम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला।

उसके बाद पुलिस टीम शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र के लोगों में कई घंटों तक हड़कंप मचा रहा। एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि कुशीनगर जिले के जटहा बाजार निवासी अलीहसन की तहरीर पर निचलौल थाने में 26 अप्रैल को आरोपी गुलशन, फिरोज, ईशा, अफरोज और फैयाज अंसारी निवासी मटरा धमउर के खिलाफ दहेज हत्या सहित कई गंभीर धाराओं के प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़ित अलीहसन ने बताया है कि 25 फरवरी 2021 को बेटी हसीरुन निशा की शादी फैयाज अंसारी निवासी मटरा धमउर के साथ किया था। शादी के बाद बेटी के दो बच्चे नाजिया और इब्राहिम ने जन्म लिया। बेटी हसीरुन निशा के पति फैयाज अंसारी विदेश में है। जो दहेज के लिए बेटी को फोन पर प्रताड़ित करने के साथ ही अपशब्द बोलते थे। इसी बीच बेटी के ससुराल वालों ने 22 अप्रैल की आधी रात को गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद बगैर कोई सूचना दिए ही शव को दफन कर दिया। हालांकि वीडियो में साफ जाहिर है कि बेटी की हत्या की गई है। मामले में न्यायालय के आदेश पर मृत हसीरुन निशा के शव को कब्र से बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन मिश्र के अनुसार मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाल आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आनंद पूर्णिमा पर गोरखपुर में भक्ति और सेवा का संगम, 22 लोगों ने किया रक्तदान

गोरखपुर।

आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा बेतियाहाता स्थित आश्रम में आनंद पूर्णिमा उत्सव बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी का जन्मोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें भक्ति, साधना और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। उत्सव की शुरुआत एक दिन पूर्व सायंकाल तीन घंटे के बाबा नाम केवलम अखंड कीर्तन से हुई। इसके साथ ही आरयू क्लब (रेनेंशा यूनिवर्सल क्लब) द्वारा सद्गुरु के रूप में श्री श्री आनंदमूर्ति जी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उनके विचारों और दर्शन पर विस्तार से चर्चा की गई। आनंद पूर्णिमा के दिन प्रातः 6:07 बजे साधना और कीर्तन के पश्चात

जयघोष के साथ जन्मोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में 22 लोगों ने रक्तदान कर मानव सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त नारायण सेवा कार्यक्रम के तहत जरूरतमंदों को सहयोग प्रदान किया गया। गोरखपुर के भुक्ति प्रधान संजय श्रीवास्तव ने कहा कि गुरुदेव द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक उत्थान के लिए जो मार्गदर्शन दिया गया है, उसका अनुसरण करने से निश्चित ही जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति संभव है। लोगों को संबोधित करते हुए मेजर साकेत ने गुरु की महिमा और उपयोगिता को समझाया। इस अवसर पर आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए फिल्टर वाटर मशीन एवं वाटर कूलर का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई और आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय वातावरण और सेवा भाव ने सभी को भावविभोर कर दिया।

दिल्ली का बुराड़ी इलाका बना अवैध शराब का हॉटस्पॉट, घरों के बाहर लगती हैं लंबी लाइनें

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी इलाका इन दिनों अवैध शराब कारोबार का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। करीब दस लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में एक भी अधिकृत शराब ठेका न होने के कारण अवैध कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। हालत यह है कि यहां की कई गलियों और कॉलोनियों में घरों से खुलेआम हरियाणा से लाई गई शराब बेची जा रही है, जिससे कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस कारोबार में शामिल

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, बुराड़ी के पांच वार्डों में दर्जनों से अधिक ऐसे घर चिन्हित किए गए हैं, जहां से नियमित रूप से अवैध शराब की बिक्री हो रही है। संत नगर, इब्राहीमपुर, जगतपुर, मिलन विहार और यमुना पुश्ता समेत कई कॉलोनियां इस गैरकानूनी गतिविधि की चपेट में हैं। यहां महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस कारोबार में शामिल बताए जाते हैं, जिससे यह नेटवर्क और मजबूत होता जा रहा है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यह पूरा कारोबार पुलिस प्रशासन की जानकारी के बिना संभव नहीं माना जा रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीट पुलिस को इन गतिविधियों की पूरी जानकारी है, लेकिन कथित सांठगांठ के चलते कार्रवाई नहीं की जाती। इससे अवैध शराब माफियाओं के हौसले और बढ़ गए हैं।

हरियाणा से कम कीमत पर लाकर बेच रहे अवैध शराब

जानकारी के मुताबिक, अवैध शराब मुख्य रूप से हरियाणा से कम कीमत पर लाई जाती है। रात के समय भारी मालवाहक वाहनों के जरिए इसे गुप्त रूप से इलाके में उतारा जाता है और फिर छोटे-छोटे नेटवर्क के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद इन्हीं घरों से 24 घंटे शराब की बिक्री जारी रहती है। अवैध शराब की आसान उपलब्धता के कारण इलाके में झगड़े और आपराधिक घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। खुले में शराब पीने और नशे में विवाद की घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में भय और असुरक्षा का माहौल है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय कॉलोनियों में जहां से अवैध शराब बेची जा रही है वहां लोगों की लाइनें लगती हैं। खासकर श्रमिक वर्ग के लोग अधिक संख्या में वहां पहुंचकर लाइन लगाकर शराब खरीदते दिखते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई की जाए और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत किया जाए। साथ ही, अधिकृत शराब ठेका खोलने या वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार करने की बात कही जा रही है, ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। समय-समय पर बुराड़ी सहित आसपास के इलाकों में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर अवैध शराब जब्त की जाती है। बीते दिनों कई मुकदमे दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। - राजा बांठिया, उपायुक्त उत्तरी जिला पुलिस।

उत्तर भारत को मिलेगी लू से राहत

14 से 16 मई के बीच मानसून की दस्तक

नई दिल्ली।

भारतीय मौसम विभाग ने मई महीने के लिए अपना ताजा पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जो देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए राहत और चुनौती दोनों लेकर आया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मई में पूरे देश में औसत वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत के संकेत मिलने लगे हैं। अनुमान है कि 14 से 16 मई के बीच मानसून अंडमान-निकोबार द्वीप समूह पहुंच जाएगा। यह सामान्य तिथि के आसपास है, जिससे इस साल मानसून के समय पर आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है।

पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लू से राहत

उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, वहां के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मई में इन राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य या उससे कम रहने का अनुमान है। इससे इस क्षेत्र में भीषण लू का असर काफी सीमित रहेगा। हालांकि, महीने के अंतिम सप्ताह में तापमान में कुछ वृद्धि देखी जा सकती है।

रात की गर्मी करेगी परेशान, इन राज्यों में हीटवेव का अलर्ट

भले ही दिन में राहत मिले, लेकिन देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जिसका मतलब है कि रातें गर्म बनी रह सकती हैं। इसके अलावा, आईएमडी ने गुजरात (विशेषकर सौराष्ट्र), महाराष्ट्र, पूर्वी तटीय राज्यों और हिमालय की तराई वाले इलाकों में सामान्य से अधिक दिनों तक लू चलने की चेतावनी दी है।

कृषि और जल प्रबंधन के लिए चुनौती

मौसम विभाग ने सचेत किया है कि मई में वर्षा का स्वरूप असमान रह सकता है। जहां उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक बारिश होगी, वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा सामान्य से कम रहने की आशंका है। कुछ इलाकों में अचानक होने वाली भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं, जो कृषि और जल प्रबंधन के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

अल-नीनो का खतरा बरकरार

मौसम के इस बदलते मिजाज के पीछे समुद्री कारकों की बड़ी भूमिका है। वर्तमान में प्रशांत महासागर में स्थिति न्यूट्रल है, लेकिन यह धीरे-धीरे अल-नीनो की ओर बढ़ रही है। यदि मानसून के दौरान अल-नीनो विकसित होता है, तो यह बारिश को प्रभावित कर उसे कमजोर कर सकता है।

बरगी क्रूज हादसे में सीएम की बड़ी कार्रवाई, पायलट समेत 3 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त, मैनेजर निलंबित

भोपाल।

बरगी जलाशय में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के बाद जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं। कार्रवाई के तहत क्रूज पायलट महेश पटेल, क्रूज हेल्पर छोटेलाल गोंड और टिकट काउंटर प्रभारी बृजेंद्र की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। वहीं, होटल मैकल रिसॉर्ट और बोट क्लब बरगी के मैनेजर सुनील मरावी को निलंबित किया गया है। इसके अलावा रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जबलपुर में बरगी जलाशय में हुए दुखद क्रूज हादसे में लापरवाही के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। क्रूज पायलट महेश पटेल, क्रूज हेल्पर छोटेलाल गोंड एवं टिकट काउंटर प्रभारी बृजेंद्र की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि हादसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि जांच के दौरान यदि अन्य जिम्मेदारों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच पहले ही शुरू की जा चुकी है। बरगी हादसे के बाद प्रशासन अब सुरक्षा मानकों और संचालन प्रक्रिया की भी व्यापक समीक्षा कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

> **9 की मौत, 6 लापता और 28 लोगों को बचाया गया**

शराब पीकर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान! अकाली दल ने वीडियो शेयर कर लगाए गंभीर आरोप

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित तौर पर शराब पीकर विधानसभा पहुंचने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अकाली दल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री कथित तौर पर नशे की हालत में विधानसभा पहुंचे। पार्टी ने इस कथित व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए इसे अनुचित बताया है।साथ ही अकाली दल ने मांग की है कि मुख्यमंत्री का सार्वजनिक रूप से डोप टेस्ट कराया जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। हालांकि, इन आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री या राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

मतगणना से पहले बंगाल में घमासान, सारी शिकायतें निराधार हैं-चुनाव आयोग

कोलकाता।

पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूम की चौबीसों घंटे सीसीटीवी निगरानी की जा रही है।

सारी शिकायतें निराधार हैं

उन्होंने कहा कि ईवीएम जिन स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई हैं, वहां लगातार निगरानी हो रही है और आम लोग भी बाहर से लगे मॉनिटर के जरिए स्थिति देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिना ठोस कारण और सबूत के आरोप लगाना उचित नहीं है। जो शिकायतें सामने आ रही हैं, वे निराधार हैं।

राजनीतिक स्तर पर भी बढ़ी सतर्कता

इस बीच राजनीतिक स्तर पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीएम ममता के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और उम्मीदवार मतगणना केंद्रों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पार्टी प्रवक्ता और बेलेघाटा सीट से उम्मीदवार कुणाल घोष ने कहा कि पार्टी के पोलिंग एजेंट्स और उम्मीदवारों को खास तौर पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। घोष ने यह भी आशंका जताई कि शाम के समय जब डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) मतगणना केंद्रों पर लाए जाते हैं, उस दौरान अनधिकृत गतिविधियों की संभावना हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपने प्रतिनिधियों को चौकन्ना रहने को कहा है।

अभिषेक बनर्जी के आरोपों को किया खारिज

साथ ही उन्होंने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के उस आरोप को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हावड़ा के उदयनारायणपुर में मतदान के दौरान केंद्रीय बलों की धक्का-मुक्की से एक बुजुर्ग मतदाता की मौत हुई। सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने बयान में इसे भय फैलाने की कोशिश बताया। उनके अनुसार, 82 वर्षीय पूर्ण चंद्र डोलुई वोट डालने के बाद उम्र संबंधी बीमारी के कारण अचानक गिर पड़े और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सीईओ ने स्पष्ट किया कि घटना के दौरान कोई धक्का-मुक्की नहीं हुई और पूरी घटना पर्यवेक्षक की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने कहा कि इस मौत का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

> **"इस बीच राजनीतिक स्तर पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीएम ममता के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और उम्मीदवार मतगणना केंद्रों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।**

सुरक्षा व्यवस्था हुई और कड़ी

कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र, जहां उत्तर और पूर्व कोलकाता की कई विधानसभा सीटों की मतगणना होनी है और ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम मौजूद हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) रूपेश कुमार ने इलाके का दौरा करने के बाद बताया कि सुरक्षा व्यवस्था अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है। साथ ही, सीसीटीवी मॉनिटर देखने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अनधिकृत पहुंच को रोका जा सके। वहीं, राज्य सरकार की मंत्री शशि पांजा ने भी केंद्र का दौरा किया और कहा कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

अखिलेश का योगी को जवाब- बोले- असली गिरगिट तो मुख्यमंत्री खुद हैं, जो नारी वंदन को नारा बनाना चाह रहे

लखनऊ।

लखनऊ में शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और सामाजिक एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय चुनौतीपूर्ण है और समाज को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इस दौरान लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर के विकास के संकल्प को भी दोहराया गया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी के गिरगिट वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद असली गिरगिट हैं, जो नारी वंदन को नारा बनाना चाहते हैं। जो बार-बार राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बयान देते हैं। अब इनके सत्ता से जाने के दिन आ गए हैं।

ये जनता का ध्यान अन्य समस्याओं से हटाना चाहते हैं

महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि यह सभी दलों की सहमति से पारित हुआ था, लेकिन भाजपा इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर विपक्ष को गलत तरीके से पेश कर रही है। उनका आरोप था कि भाजपा इस मुद्दे को नारे के रूप में इस्तेमाल कर रही है, ताकि जनता का ध्यान अन्य समस्याओं से हटाया जा सके। उन्होंने परिसीमन और संशोधन बिल को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि लंबे समय से डेटा एकत्र कर राजनीतिक रणनीति बनाई जा रही है। कानून-व्यवस्था पर हमला करते हुए उन्होंने 'बुलडोजर नीति' को कठघरे में खड़ा किया और हरदोई व वाराणसी की घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने स्मार्ट मीटर योजना, गेहूं खरीद में देरी, श्रम कानूनों में बदलाव और अयोध्या मास्टर प्लान में बार-बार संशोधन जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं बना रही है। कुल मिलाकर, उन्होंने भाजपा को जनविरोधी बताते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और सरकार के दिन गिने हुए हैं।

दिल्ली में स्कूलों की मनमानी पर रोक -एडवांस फीस वसूली पर लगा प्रतिबंध, अब हर महीने ही लेनी होगी पेमेंट

नई दिल्ली।

शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी निजी, गैर-सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है। अब स्कूलों को फीस सख्ती से हर महीने ही लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

शिक्षा निदेशालय को मिल रही थीं शिकायतें

निदेशालय ने 30 अप्रैल के अपने आदेश में बताया कि उसे अभिभावकों से कई शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों में कहा गया था कि कुछ स्कूल दो महीने, तिमाही या अन्य अग्रिम आधार पर फीस देने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे परिवारों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ रहा था। इस निर्देश में दोहराया गया है कि स्कूल एक किस्त में एक कैलेंडर माह से अधिक की फीस का भुगतान अनिवार्य नहीं कर सकते। यह कदम पहले के निर्देशों और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप है। उच्च न्यायालय ने फीस संग्रह को अभिभावकों के लिए सुविधाजनक और उचित बनाने पर जोर दिया था। हालांकि, अभिभावक अपनी इच्छा से एक माह से अधिक की फीस एक साथ जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन पर कोई दबाव या प्रलोभन नहीं होना चाहिए।

प्रवेश के लिए अग्रिम फीस नहीं

आदेश में कहा गया है कि कोई भी स्कूल प्रवेश, निरंतर नामांकन या किसी भी छात्र सेवा के लिए अग्रिम फीस भुगतान को शर्त नहीं बनाएगा। सभी स्कूलों को इस आदेश को अपनी सूचना पट्टियों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। उन्हें सात कार्य दिवसों के भीतर अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर भी इसे अपलोड करना होगा। यह सुनिश्चित करना है कि सभी अभिभावकों और हितधारकों को इसकी जानकारी हो।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का हवाला देते हुए निदेशालय ने चेतावनी दी है। नियमों का पालन न करने पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। इसमें मान्यता रद्द करना या स्कूल प्रबंधन पर कब्जा करना भी शामिल है। शिक्षा निदेशालय का यह कदम शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए है। इसका उद्देश्य अभिभावकों, विशेषकर निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करना है।

> **निदेशालय ने 30 अप्रैल के अपने आदेश में बताया कि उसे अभिभावकों से कई शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों में कहा गया था कि कुछ स्कूल दो महीने, तिमाही या अन्य अग्रिम आधार पर फीस देने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे परिवारों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ रहा था। इस निर्देश में दोहराया गया है कि स्कूल एक किस्त में एक कैलेंडर माह से अधिक की फीस का भुगतान अनिवार्य नहीं कर सकते।**

ईरान पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर सकता है अमेरिका

वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रम्प को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक एडमिरल ब्रैड कूपर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रम्प के साथ बैठक में ये विकल्प पेश किए। इसमें बताया गया कि अगर ट्रम्प दोबारा हमले का फैसला लेते हैं, तो एक 'छोटा लेकिन बहुत ताकतवर हमला' किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, उसके नेता और अहम ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को निशाना बनाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय कुछ नए और एडवांस हथियार इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहा है। इनमें 'डार्क ईगल' नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। यह मिसाइल करीब 2,000 मील (करीब 3,200 किलोमीटर) दूर तक निशाना साध सकती है और ईरान के बचे हुए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को टारगेट कर सकती है।

पंजाब में है आज राजनीतिक अस्थिरता- नायब सिंह सैनी

पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर विकसित भारत के संकल्प की तर्ज पर विकसित पंजाब बनाने का किया जाएगा काम- मुख्यमंत्री सैनी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज पंजाब की राजनीति एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां सत्ता, स्थिरता और जनहित के बीच गहरा संघर्ष दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीति में अस्थिरता बढ़ रही है। पंजाब को आज जरूरत है एक ऐसी डबल इंजन सरकार की, जो केवल वादे न करे, बल्कि उन्हें पूरा करने की क्षमता भी रखे। जरूरत है एक ऐसे नेतृत्व की, जो निर्णय लेने से न डरे, जो जनता के हित को सर्वोपरि रखे और जो देशहित में काम करे। यह सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प की तर्ज पर विकसित पंजाब बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पंजाब के गोबिंदगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी गोबिंदगढ़ का इतिहास हमें यह सिखाता है कि संघर्ष और संकल्प से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यह क्षेत्र सदियों से व्यापार, संस्कृति और सामाजिक समरसता का केंद्र रहा है। यहां विभिन्न समुदायों ने मिल-जुलकर एक ऐसी विरासत का निर्माण किया है, जिसमें एकता और भाईचारे की भावना सर्वोपरि है। इतिहास के अनेक उतार-चढ़ावों का साक्षी रहा यह नगर हर चुनौती के बाद और अधिक मजबूत होकर उभरा है। चाहे वह सामाजिक परिवर्तन का दौर रहा हो या आर्थिक बदलावों का समय हो, मंडी गोबिंदगढ़ ने हर परिस्थिति में अपनी पहचान और अपने आत्मबल को बनाए रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहर देशभर में स्टील टाउन के नाम से भी विख्यात है। यहां के उद्योग पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। विडंबना है कि आज मंडी गोबिंदगढ़ का उद्योग कई गंभीर संकटों से जूझ रहा है। महंगी बिजली और नीतिगत अस्थिरता ने यहां के उद्योगों की रीढ़ को कमजोर किया है। कई छोटे और मध्यम उद्योग बंद होने की कगार पर हैं और हजारों मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, यह उन परिवारों की पीड़ा है, जिनकी रोजी-रोटी इस उद्योग से जुड़ी हुई है। जब फैक्ट्री बंद होती है, तो केवल मशीनें नहीं रुकतीं, बल्कि घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के अपने संकल्प-पत्र के 217 में से 60 वादों को डेढ़ साल में ही पूरा कर दिखाया है। यही नहीं, 157 वादों पर काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बहनों-बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' शुरू की गई है। इस योजना के तहत 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक लगभग 10 लाख बहन-बेटियों को 1 हजार 38 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में किसानों की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 79 हजार 317 करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बुजुर्गों को 3200 रुपये प्रति माह पेंशन दे रही है। इस पेंशन का 50 लाख बुजुर्गों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 'बिना पर्ची और बिना खर्ची' के 2 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी करें कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पंजाब के कितने युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब से नशा खत्म करने की बात कही थी, लेकिन आज पंजाब विधानसभा में दिए जा रहे भाषण के समय मुख्यमंत्री स्वयं नशे में दिखाई दिए।